Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

उदारीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. प्रतिमा बनर्जी *

*** प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्वशासी स्नातकोतर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत**

प्रस्तावना – उदारीकरण विश्व के विभिन्न देशो के बीच आर्थिक संबंधो, सहयोग और विनियम को व्यापकता तथा गहराई देने की प्रक्रिया है। व्यवहार मे यह विश्व व्यापार को निर्बाध विस्तार देने की प्रक्रिया है। दो देशो के आपसी रिश्तोय के रास्ते में उन देशो की प्रभुसत्ता, देशी कानून, परंपरांए, भू – सामरिक प्राथमिकताएं और सांस्कृतिक मान्यताएं अवरोधकों की भांति आती रहती है अत: ऐसे अवरोधो से समझौता करना, उन्हे लांघना या बदलना, किसी न किसी तरह पार करना आवश्यक है इसलिए आर्थिक सहयोग और रिश्तों की गहराई तथा व्यापकता के दायरे में कही न कही राजनैतिक सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी आते है।

अपने देश की आर्थिक विकास दर को उच्च बनाये रखने के उद्देश्य की संकल्पना लिए हुए विकासशील राष्ट्रो ने अपने यहां विकसित राष्ट्रो को पूंजी निवेश की अनुमति दी और विकसित राष्ट्रो ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया किन्तु इसके पीछे विकसिंत राष्ट्रो की पृष्ठभूमि में उनके लिए यह एक आवश्यक मजबूरी बन गयी थी कि वे अन्य राष्ट्रों में अपने पांव फैलाये। वस्तुत: विकासशील राष्ट्रो बढ़ते औद्योगीकरण से विकसित राष्ट्रो के निर्यातों,औद्योगिक उत्पादन व रोजगार में तेजी से गिरावट आने लगी और वर्ष 1988 के बाद से वे भयानक मंदी मे फंस गये। 24 औद्योगिक राष्ट्रों में 3 करोड 60 लाख लोग बेरोजगार हो गये। शक्तिशाली राष्ट्रो की बड़ी कंपनियों और बैको का दिवाला निकल गया। ऋणात्मक विकास दर और उससे बड़ी मात्रा में सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात् अपने औद्योगिक पुनरूद्धार व रोजगार विकास हेतु विकसित राष्ट्रों ने 'वैश्वीकरण', 'भूमण्डलीकरण', उदारीकरण जैसी संकल्पना प्रस्तुत की और विकासशील राष्ट्रो पर यह दबाव डाला गया कि वे केवल कच्चे माल को उत्पन्न करे और निर्मित माल का उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनी करे मुद्राकोष, विश्व बैक व अन्य सहायता क्लबो को निर्देश दिये गये कि वे विकासशील राष्ट्र आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम व निर्यातो को अनुदान बंद करे। आयात से प्रतिबंध हटाकार आयात शुल्क समाप्त करे या घटाएं और विदेशी कंपानियो को पूंजी निवेश व मुनाफा बाहर ले जाने की पूरी छूट दे, इन शर्तो को पूरा करने पर ही उन्हे ऋण दिया जायेगा। कृषि, बागवानी, मत्सयाखेट, पशु – पालन उत्पादों, मांस निर्यातो को प्रोत्साहन दिलाकर लगभग 50 से अधिक विकासशील देशो की मुद्रा का भी अवमूल्यन हुआ जिससे विकसित देशो को सभी खाद्य पदार्थ एवं खनिज कम मूल्य पर उपलब्ध हो। इस तरह समाजवाद और पूंजीवाद ने शनै: शनै: उदारीकरण के नाम पर विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक बाजार पर कब्जा कर लिया है। आर्थिक पुननिर्माण एवं व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से ही विकसित देशो ने चार प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओ का गठन किया जिसने बिना किसी बाधा व विरोध के विश्व में मुक्त बाजार का मार्ग खोल दिया। ये संस्थाएं है–

1. ब्रेटन बुड्स एक्चेंस रेट सिस्टम
2. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड)
3. विश्व बैक (वर्ल्ड बैक)
4. गैट (जी.ए.टी. जनरल एग्रीमेंन्ट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ (आयातकर)

इन संस्थाओं की व्यापार नीतियों, वैश्विक व्यापार कार्य यानि भूमंण्डलीय कार्य व्यापार द्वारा सभी को आर्थिक सम्पन्नता, समृद्धि प्रदान करना है। यद्यपि इसमे पूरी पारदर्षिता नही है, फलत: विकासशील देशो के नागरिको का भरपूर शोषण व्यापारिक कंपानियों द्वारा किया जाता रहा है। किन्तु इसे नजर अंदाज कर भारत सहित दुनिया के तमाम देशों ने गैट समझौते को स्वीकार कर अपने यहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अत्यन्त सुविधा प्रदान कर इस बात की कल्पना प्रस्तुत की कि उदारीकरण अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश के नागरिको की मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति आसानी से हो सकेगी और देश आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ेगा।

सन् 1991 – 92 के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से शुरू हो गयी, ताकि भूमण्डलीकरण की दौड़ मे भारत की अपनी भूमिका निभा सके। यद्यापि उदारीकरण के पश्चात् भारत की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार हुआ, भुगतान – संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ, विदेशी मुद्रा में भारी बढ़ोतरी हुई और विदेशी मुद्रा का पूंजी निवेश हुआ।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र मे विशेषज्ञों और प्रशिक्षित युवाओ के लिए रोजगार के अवसरो में वृद्धि हुई। विदेशो में रोजगार के अच्छे विकल्पों के मार्ग खुले। समाज के सभी वर्गो विशेषकर उच्च– मध्यम वर्ग को अवसर मिले। आवश्यकता से अधिक आय ने उपभोगत्तावाद को जन्म दिया। नई प्रोद्योगिकी वाली आकर्षक वस्तुओ की मांग बढ़ी। परिवहन में नई तथा आधुनिक कारों, फैशन में आधुनिक बनावट और सौन्दर्य प्रसाधन की अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तुएं भारत सहित एशिया के बाजारो मे छा गयी। आटो – मोबाइल क्षेत्र में भारी पूंजी निवेश हुआ।

बाहरी तौर पर देखने से पता चलता है कि उदारीकरण अपननाने से देश के वित्तीय हालात में काफी सुधार हआ है। रोजगार के अवसर खुलने से लोगो की आमदनी बढ़ी है और मध्यम वर्ग बड़ी तेजी से उच्च वर्ग में शामिल हो रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस उदारीकरण की प्रकिया अपनाने

के बाद एवं विदेशी पूंजी निवेश के बाद देश के समक्ष अनेक तरह की चुनौतियां खड़ी हो गयी है।

उदारीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न चुनौतियॉ :

1. उदारीकरण के बाद हुए उच्च प्रोद्यौगिकी विकास से विकासशील देशों का व्यापारिक शोषण बढ़ा है जिससे उत्पन्न ऋणजाल ने विकासशील देशों के समक्ष आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गंभीर चुनौती खड़ी की है।
2. रोजगार के तमाम विकल्प भले ही खुले है। किन्तु नित नयी तकनीक का सामना करने की, और अपने आप को खड़ा रखने की चुनौती भी है साथ ही कामगारों में अनिश्चिता की भावना बढ़ी है।
3. उदारीकरण विकासशील देशों के पूर्ण निजीकरण का लक्ष्य लेकर आया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजी का गुलाम बनाने से रोकना आज एक बड़ी चुनौती है।
4. आज भारत में उपभोक्तावाद, स्वार्थपरता, धन का केन्द्रीकरण, पर्यावारण प्रदूषण, धन एवं आर्थिक शक्ति की भयंकर विषमता इसी उदारीकरण प्रक्रिया की देन है।
5. विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनो पर विकसित देशों का नियंत्रण हो चुका है फलत: वे उसका भरपूर दोहन एवं शोषण कर रहे है। कृषि क्षेत्रो मे बीजों चिकित्सा क्षेत्र मे दवाओं, आटो – मोबाइल क्षेत्र में उसके कलपुर्जे आदि पर बहुराष्ट्रीय कंपनियो का दबदबा होने से नित नई चुनौतियां सामने आ रही है।
6. प्राकृतिक, मानवीय एवं पूंजीगत क्षेत्र में विदेशी प्रभाव बढ़ने से विकासशील देशों को मानवीय मूल्य, सभ्यता एवं संस्कृति के समक्ष अपने आप को बनाये रखने की चुनौती खड़ी हो गयी है।

समस्याएं – चुनौतियां जब दीर्घकालिक हो जाती है तो वह समस्या का रूप धारण कर लेती है। सन् 1991 – 92 मे आए उदारीकरण के फलस्वरूप अनेक चुनौतियां सामने दिखने लगी किन्तु धीरे – धीरे इन्होंने समस्या का रूप धारण कर भारतीय समाज, संस्कृति, सभ्यता, धर्म सभी क्षेत्रो मं चतुर्दिक हमला कर दिया है। उदारीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप अनेक समस्याएं देखने को मिल रही है। ऊपरी चमक – दमक के भीतर एक भयावह अंधेरा अपने पांव पसार रहा है। कुछ प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है :

1. उदारीकरण के फलस्वरूप सर्वप्रथम स्थानीय उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग बड़ी तीव्र गति से बंद हुए।
2. मानवीय सरोकरों और संवेदनाओं पर पूंजी की सत्ता हावी होती गयी।
3. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, विश्व बैंक ने विकासशील देशों को ऋण देने के लिए विकसित देश की किसी विशेष कंपनी को आयात शुल्क और व्यापार शुल्क में भारी छूट देने जैसा नियम बनाकर विकासशील देशों को मजबूर करना प्रारम्भ किया।
4. विश्व व्यापार में भागीदारी बढ़ने से शक्तिशाली पूंजीवादी देशों पर गरीब देशों की निर्भरता बढ़ी है।
5. उदारीकरण के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था मे विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओ का दखल बढ़ा है।
6. उदारीकरण के बाद से उच्च वर्ग – मध्यमवर्ग एवं निम्न वर्ग के बीच आर्थिक असामनता की दूरी निरंतर बढ़ रही है।
7. उदारीकरण की प्रक्रिया ने निजीकरण को बढ़ावा देकर सरकारी हस्तक्षेप को खत्म करके राष्ट्रीय सम्प्रभुता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरे पैदा किये हैं।
8. आज विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से चलायी जा रही भौतिक एवं आर्थिक प्रक्रिया के प्रभाव से पूंजीवाद देश विकासशील देशों पर सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापना कर रहे है।
9. सन् 2000 तक देश मे कार्यरत 317 बडी कंपनियो ने 25 हजार करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा बाहर भेजी है जबकि उदारीकरण से पूर्व देश से बाहर भेजी गयी विदेशी मुद्रा 4 हजार करोड़ से भी कम थी।
10. भारत की जैव विविधता नष्ट हो रही है जबकि उसके जैव द्रव्य प्रत्यारोपण के पेटेंट विदेशी कम्पनियां करा रही है ।
11. विदेशी पूंजी निवेशी को प्रोत्साहन देने एवं विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर नियंत्रण समाप्ति तथा उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने से भारतीय उद्योग नष्ट हुए हैं तथा देशी उद्योगों पर बैंक ऋण पर ब्याज दर बढ़ी है।
12. जन उपयोगी सेवाओं पानी, बिजली, पेट्रोल, गैस दवा, खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादों पर सब्सिडी कम होती जा रही है फलत: इनके दामों मे लगातार वृद्धि हो रही है।

सुझाव – इस प्रकार कहा जा सकता है कि उदारीकरण के फलस्वरूप कई तरह की चुनौतियां सामने आयी है जो गंभीर समस्या का रूप ले चुकी है किन्तु इसके समाधान के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय करने वे लाभकारी सिद्ध हो सकती है। कुछ प्रमुख सुधार के उपाय इस प्रकार है –

1. सर्व प्रथम देशी उद्योगों, कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज पर इच्छुक उद्यमी को ऋण उपलब्ध होना चाहिए साथ ही विदेशी कंपानियों के ऋण पर ब्याज दर बढ़ाना चाहिये।
2. स्कूल, कालेजो में उत्तम व्यावसायिक एवं तकनीक सिखाने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं स्थापित कर प्रत्येक छात्र को किसी एक तकनीकी कौषल में आवश्यक रूप से पारंगत करना चाहिए।
3. पेट्रोल,गैस के स्थान पर बायोटेक्निक के संयंत्रों को बढ़ावा देना चाहिए।
4. कुछ स्थानो पर स्वरोजगार समूह सफल रहे है। इन्हे सरकारी संरक्षण देकर गांवो से शहरो की ओर का पलायन रोका जा सकता है।
5. कृषि उत्पादों पर सब्सिडी बढ़ाकर कृषि को प्रोत्साहित करने के साथ ही कृषकों को सही समय पर उनकी फसलों को उचित सरकारी मूल्य मिले।
6. विदेशी बीजों, रसायनों, मशीनों का प्रयोग रोककर देशी उपाय एवं तकनीकी को बढ़ावा दिया जाय।
7. पाश्चात्य उपभोग प्रतिमानो को बढ़ावा देने के बजाय विकासशील देशों के लोगों की मूल आवश्कयताओं की पूर्ति पर ध्यान दिया जाय।
8. कृषि बागवानी वानिकी, हस्तशिल्प पारंपरिक कुटीर, लघु उद्योगो द्वारा तथा 35 प्रतिशत जनता की आवश्यकता पूर्ति स्थानीय संसाधनो से की जाय। इसके लिए विकेन्द्रित नियोजन से देश को विकसित किया जाय।
9. विदेशी कंपनियों एवं पाष्चात्य भोगवादी संस्कृति का पूर्ण बहिष्कार हो।
10. आयात में की जाने वाली भारी छूट में कटौती कर निर्यात को बढ़ावा दिया जाय।
11. उदारीकरण के फलस्वरूप विदेशी निवेश सीमा में अप्रत्याशित छूट से

भारतीय वस्तुओं के बाजारों पर विदेशी कंपानियो के एकाधिकारी को तत्काल प्रभाव से कम करना आवश्यक है।

12. उदारीकरण द्वारा आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए इसे योजनाबद्ध तरीके से अपनाएं जाने की आवश्यकता है ताकि राष्ट्रीय आय, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं निर्यातो मे वृद्धि हो सके।

निष्कर्ष के रूप मे हम कह सकते है कि उदारीकरण से आर्थिक विकास में आर्षिक रूप से भले ही सकरात्मक प्रभाव पड़ा हो, किन्तु उसको अपनाने के बाद विकासशील देशो के समक्ष अपने अस्तित्व को बनाये रखने की चुनौती और उससे उत्पन्न समस्या बढ़ी ही है। कई देश उदारीकरण की तेज आंधी में एक सही झटके में अपनी जडो से उखड़ गये। पूर्व महाशक्ति सोवियत संघ सहित पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों के समक्ष आर्थिक अराजकता का दौर प्रारम्भ हो गया हांलाकि भारत की जड़े भले ही मजबूत है किन्तु उस पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। उदारीकरण प्रक्रिया को योजनाबद्ध तरीके से तथा राष्ट्रहित को ध्यान मे रखकर ही अपनाये जाने की आवश्यकता है। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत से आयतित सामान पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की योजना पर ऐलान किया है इसका प्रभाव निकट भविष्य में हमे देखने को मिलेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संदीप वासलेकर, 'नये भारत का निर्माण', प्रभात पब्लिकेशन, दिल्ली 2012 पृ0 -102-103.
2. कुसुमलता केडिया व अरूणा सिंह, 'दृष्टिदोष तो विकल्प कैसे', सर्व सेवा संघ, वाराणसी 1994 पृ0 - 29.
3. डॉ0 भागवती प्रकाश शर्मा, 'आर्थिक वैश्वीकरण', स्वदेशी जागरण प्रकाशन, दिल्ली 2005 पृ0 2-3.
4. वही पृ0 - 16.
5. कुमुद शर्मा, 'भूमण्डलीकरण और मीडिया', ग्रंथ अकादमी, दिल्ली पृ0 2009 - 36.
6. दैनिक भास्कर पत्रिका, दिनांक 20 अगस्त 2025.

****